

एलआईसी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए

सार्थक वेतन पुनर्निर्धारण व पेंशन के एक और विकल्प के लिए संयुक्त संघर्ष समिति ने किया आर-पार की लड़ाई का ऐलान

प्रिय साथियों/मित्रों,

● 14 अक्टूबर 2015 को एक दिन की हड़ताल

● 19 और 20 नवम्बर 2015 को दो दिन की हड़ताल

● यदि आवश्यक हो तो आगे और सघन कार्रवाई

जैसा कि आपको विदित है एलआईसी में यूनियनों के संयुक्त मोर्चा की 29 सितम्बर 2015 को पुणे में बैठक सम्पन्न हुई। यह बैठक वेतन पुनर्निर्धारण और पेंशन के एक और विकल्प के लिए अब तक के संघर्ष की समीक्षा करने और इन दो मांगों को प्राप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई का कार्यक्रम तैयार करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक ने संतोष व्यक्त किया कि मुंबई में 19 अगस्त 2015 को सम्पन्न पिछली बैठक के संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रमों के निर्णयों को कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों ने उत्साह से अनुरोध याचिका पर हस्ताक्षर किए जिसमें, वित्तमंत्री को हस्तक्षेप करने और कार्यबल की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एलआईसी की देयक क्षमता के आधार पर एलआईसी में वेतन पुनर्निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया गया। इन हस्ताक्षरों के जरिये वित्तमंत्री को यह जानकारी दी गई कि एक कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद, एलआईसी ने अच्छा प्रदर्शन किया और वह बाजार पर हावी रहते हुए राष्ट्र निर्माण गतिविधि के लिए सीमित संसाधनों को उपलब्ध करा रही है। कर्मचारियों ने वित्तमंत्री को उनकी स्वयं की उन टिप्पणियों को याद दिलाया कि, एलआईसी एक उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि जो उद्योग अच्छी तरह से कार्य करता है, तो उसका लाभ कर्मचारियों को भी प्रवाहित होना चाहिए। समूचे देश से हस्ताक्षर याचिकाएं 23 सितम्बर 2015 को वित्तमंत्री को भेजी गयी है।

संयुक्त बैठक ने नोट किया कि 8 जुलाई 2015 की हड़ताल को एलआईसी प्रबंधन के अनुरोध पर इस आश्वासन के आधार पर स्थगित कर दिया गया था कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया के लगभग 3 महीने के बाद भी, कोई प्रगति होती नहीं दिख रही है और कब वार्ता बुलाई जाएगी और मांगों का समाधान किया जाएगा, यह अनिश्चित है। बैठक ने नोट किया कि एलआईसी प्रबंधन के प्रयासों के बावजूद, सरकार के कठोर रूख को संघर्ष के बगैर नहीं तोड़ा जा सकता है। सरकार का रूख बिल्कुल अनुचित है और सामूहिक सौदेबाजी और औद्योगिक लोकतंत्र दोनों का मजाक है। यह एलआईसी के कर्मचारियों-अधिकारियों के यूनियनों को कतई स्वीकार्य नहीं है। एलआईसी में पेंशन पूरी तरह से वित्त पोषित और वहनीय है। इसलिए, वेतनमानों को सीमित करने की स्थिति थोपना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसी तरह, एक और पेंशन विकल्प पर सरकार का रूख भी अनुचित और अन्यायपूर्ण है।

इसलिए, संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया कि वेतन पुनर्निर्धारण में अब कोई भी देरी नहीं की जा सकती है। इस मुद्दे पर गतिरोध को कार्रवाई के तेज रूपों के माध्यम से ही तोड़ा जा सकता है। इसलिये, बैठक में सर्वसम्मति से 14 अक्टूबर को एक दिवसीय हड़ताल एवं 19 और 20 नवम्बर 2015 को दो दिन की हड़ताल का निर्णय लिया गया। हड़ताल की ये तिथियां इस अवधि के दौरान त्यौहारों, छुट्टियों और चुनावों को देखकर तय की गई है। संयुक्त मोर्चा ने यदि स्थिति की मांग हो तो सम्पूर्ण टकराव सहित आगे के कार्यक्रमों के बारे में फैसला करने के लिए नागपुर में 29 नवम्बर 2015 को फिर से मिलने का फैसला किया। पहले के निर्णय के

अनुसार 'कार्यालय समय के बाद कोई काम नहीं' का आन्दोलन जारी रहेगा। हड़ताल की कार्यवाही का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

1. भोजनावकाश में प्रदर्शन - 06 और 13 अक्टूबर 2015
2. एक दिन की हड़ताल - 14 अक्टूबर 2015
3. भोजनावकाश में प्रदर्शन - 16 नवम्बर एवं 18 नवम्बर 2015
4. दो दिन की हड़ताल - 19 और 20 नवम्बर 2015

मध्य क्षेत्र में उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त शाखा, मंडल एवं क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त आम सभायें आयोजित करने तथा मंडल स्तर पर संयुक्त पत्रकार वार्तायें आयोजित करने का भी आह्वान किया गया है।

हम, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आन्दोलन के कार्यक्रम का समर्थन करने और सफलतापूर्वक उपरोक्त कार्यक्रम सम्पन्न करने हेतु सभी तैयारी करने का अनुरोध करते हैं। संयुक्त मोर्चा को पूरा भरोसा है कि हमारे रास्ते में आने वाले वर्तमान गतिरोध को संघर्ष के माध्यम से तोड़ा जा सकता है तथा एक अच्छा वेतन पुनर्निर्धारण और एक अन्य पेंशन विकल्प हासिल करने में हमें अवश्य सफलता मिलेगी।

(कृपया ध्यान दें कि एन.एफ.आई.एफ.डब्ल्यू.आई. ने उपरोक्त कार्यक्रम के लिए अपना पूर्ण समर्थन देते हुए उनके संगठनात्मक बाधाओं की वजह से हड़ताल कार्रवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। हालांकि, वे संयुक्त फोरम के हिस्से के रूप में अन्य सभी कार्रवाई कार्यक्रमों में भाग लेंगे)

साथियों, सार्थक वेतन पुनर्निर्धारण व पेंशन के एक और विकल्प की मांग पर संघर्ष अपने निर्णायक दौर में है। सरकार व प्रबंधन की हठधर्मिता ने हमें आर-पार की लड़ाई के लिये मजबूर कर दिया है। एलआईसी जैसे राष्ट्रीयकृत उद्योग में स्वतंत्र रूप से इन सवालों का अपनी क्षमताओं के अनुरूप समाधान की स्वायत्तता से इंकार करने का भारत सरकार का रूख स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये, इस न्यायपूर्ण संघर्ष में अपनी पूरी शक्ति के साथ संघर्ष हमें सुनिश्चित करना है। हम समस्त अधिकारी-कर्मचारी साथियों से इसलिये इन संघर्ष के भावी कार्यक्रमों को मध्यक्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से कामयाब बनाने जुट जाने और 14 अक्टूबर को एक दिवसीय तथा 19 एवं 20 नवम्बर 2015 की दो दिवसीय हड़ताल को सफल करने की अपील करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अब तक के संघर्ष में जो अभूतपूर्व एकता का हमने प्रदर्शन किया है उसी अनुरूप इन आन्दोलनों में भी आपका हमें सम्पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

अभिवादन के साथ,

आपके विश्वासी,


के पी गुप्ता
क्षेत्रीय महासचिव

Fed. of LIC CI I Officers Assn.


नीशाद अली
क्षेत्रीय रेसीडेंट महासचिव


National Orgn. Of Insurance Officers (NOINO)


ललित दीक्षित
क्षेत्रीय महासचिव

National Fed. of Ins.Field Workers (NFIFWI)


बी सान्याल
क्षेत्रीय महासचिव

All India Insurance
Employees' Association


सत्येन्द्र पाल सिंह
क्षेत्रीय महासचिव
National Organisation
of Insurance Workers (BMS)


निधि चदढा
क्षेत्रीय महासचिव
National Organisation
of Insurance Workers


नारान सैनी
क्षेत्रीय महासचिव
All India Life Insurance
Employees' Association